

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संभागीय खाद्य नियंत्रक,
कुनायूँ/गढ़वाल सम्भाग।
हल्द्वानी/देहरादून।
5. अपर निबंधक,
उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौड़ी/
देहरादून/नैनीताल/धम्मावत।
4. निदेशक,
गण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

देहरादून दिनांक 02 मार्च, 2007

विषय:- रबी कृषि विपणन वर्ष 2007-08 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गोहूँ कृषि की व्यवस्था।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी खरीद वर्ष 2007-08 में कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोहूँ का कृषि निम्नांकित अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा:-

2. गोहूँ का मूल्य

भारत सरकार के पत्रांक एफ0स0-6-6/2006-एफ0ई0एस10-ई0एस10 (पार्ट-1), दिनांक-03 नवम्बर, 2006 द्वारा रबी विपणन सत्र 2007-08 के लिए अच्छे औरत किस्म के गोहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु 750.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है,

फसल	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्तल
गोहूँ	750.00

6. गोहूँ की गुण विनिर्दिष्टियाँ

उपरोक्त मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7-1/2007-S&1, दिनांक- 07 मार्च, 2007 द्वारा निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार गोहूँ कृषि किया जायेगा जो (परिशिष्ट-1), पर संलग्न है।

7. कय एजेन्सियों एवं खरीद का लक्ष्य

(क) शासन द्वारा रबी कय योजना वर्ष 2007-08 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ कय करने हेतु निम्नलिखित कय एजेन्सियों नामित की गयी है। कय एजेन्सियों तथा उनके द्वारा खोले जाने वाले कय केन्द्र तथा एजेन्सियों के लिए निर्धारित कार्यकारी लक्ष्य निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	कय एजेन्सी का नाम	केन्द्रों की संख्या	लक्ष्य भी० टन में
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	34	20,000
2.	भारतीय खाद्य निगम	32	30,000
3.	उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ	170	1,30,000
	योग:-	236	1,80,000

गेहूँ का कय विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 85 हजार भी० टन का संग्रहण स्टेट पूल में तथा शेष कय किया जाने वाला गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य संस्थाएँ गेहूँ कय का कार्य करने में रुचि दिखाती हैं और आवेदन करती हैं तो गुण दोष के आधार पर उन संस्थाओं को गेहूँ कय कार्य करने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा कय केन्द्र पर लाये गये प्रत्येक कृषक का गेहूँ खरीदा जायेगा, चाहे वह सहकारी समिति का सदस्य हो अथवा न हो। उनके द्वारा ऐसी भी शर्त नहीं लगायी जायेगी कि पहले किसान द्वारा उनके बकाया का भुगतान किया जाये, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

8. समय सारिणी

रबी विपणन वर्ष 2007-2008 में गेहूँ कय हेतु आवश्यक व्यवस्था विषयक समय सारिणी, शासनादेश संख्या-73/07-XIX-2/13 वि०/06/खाद्य/2006 टी०सी०, दिनांक-14 मार्च, 2007 के द्वारा समस्त सम्बन्धित को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सभी संबंधित यथासमय तदनुसार वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

9. जिला खरीद अधिकारी का नामांकन

उत्तराखण्ड में रबी विपणन सत्र 2007-2008 में गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी एवं सुचारु ढंग से सम्पादित कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक "जिला खरीद अधिकारी" नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिला अधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा, जिसका गेहूँ खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने का दायित्व होगा एवं जो विभिन्न कय एजेन्सियों एवं भण्डारण एजेन्सी के बीच समन्वय भी स्थापित करेगा।

.....3.....

10. क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं स्थापना

जनपद में गेहूँ के उत्पादन एवं विपणन योग्य अतिरिक्त (Marketable Surplus) की परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में गेहूँ के आवक का आंकलन स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा सभागीय खाद्य नियंत्रक के सहयोग से किया जायेगा। किसानों के विपणन योग्य सरप्लस की मात्रा को ध्यान में रखते हुए गांवों के सम्बन्धीकरण के आधार पर क्रय केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित प्राणों की किसानवार सूचियाँ सम्बन्धित सभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी एवं क्रय संस्थाएँ यह सुनिश्चित करेंगी कि गेहूँ खरीद का कार्य किसी भी प्रकार प्रभावित न हो। यदि किसी किसान का नाम सूची से छूट गया हो तो आवश्यक जाँच के बाद जिलाधिकारी उसके गेहूँ को खरीदने की अनुमति दे सकते हैं। क्रय केन्द्र खोलने में यह विशेषकर ध्यान देने योग्य है, कि एक ही स्थान पर आवश्यकता से अधिक सख्या में क्रय केन्द्र न खोले जायें। ऐसी भी स्थिति न उत्पन्न हो कि किसानों को अपने खेतों से बहुत दूर गेहूँ ले जाना पड़े क्योंकि इससे "डिस्ट्रेस सेल" के अवसर उपलब्ध होंगे। अतः क्रय केन्द्रों के स्थान निर्धारित करते समय यह अवश्य ध्यान में रखा जाये कि 10 कि०मी० की परिधि में कम से कम एक क्रय केन्द्र अवश्य खोला जाये। वर्तमान खरीद वर्ष 2007-2008 में जिले में खरीद कार्य हेतु नामित क्रय एजेंसियों के अधिकारी अपने क्रय केन्द्रों की सूची जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एवं शासन की नीति के अन्तर्गत गेहूँ क्रय केन्द्रों के स्थान तय करेंगे। सभी क्रय एजेंसियाँ जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर क्रय केन्द्र खोलना सुनिश्चित करेंगी। क्रय केन्द्र निर्धारित स्थान पर विलम्बतम 01 अप्रैल, 2007 तक निश्चित रूप से खुल जाय तथा खरीद हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित कर ली जायें। क्रय केन्द्र निर्धारित करते समय यह अवश्य देख लिया जाय कि विगत वर्षों में जिन क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद नहीं हुई है एवं इस वर्ष भी उन केन्द्रों पर गेहूँ आने की सम्भावना न हो तो उन क्रय केन्द्रों को अनावश्यक रूप से खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि उससे उन केन्द्रों पर स्टॉफ की तैनाती एवं व्यवस्था का औचित्य नहीं रह जाता है।

यदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित गेहूँ क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में गेहूँ की आवक नहीं होती है एवं गेहूँ का स्थानीय मण्डियों में बाजार भाव समर्थन मूल्य के आस-पास रहता है तो गेहूँ खरीद के लक्ष्य की पूर्ति करने के निमित्त क्रय एजेंसियाँ सब सेंटर स्थापित कर सकती हैं एवं आवश्यकता समझे जाने पर गेहूँ खरीद कार्य हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन से मोबाईल टीम भी गठित कर सकती हैं, ताकि गेहूँ के बड़े उत्पादकों से उनके खेत/खलिहान से भी गेहूँ की खरीद की जा सकें। क्रय एजेंसियों द्वारा सब-सैंटर खोलने अथवा मोबाईल टीम गठित करने पर उनका अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय एवं उसकी सूचना शासन/खाद्यायुक्त/सम्बन्धित सभागीय खाद्य नियंत्रक/भारतीय खाद्य निगम को अवश्य भेजी जाय।

11. क्रय एजेंसियों को बोरे उपलब्ध कराना

(1) भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गेहूँ खरीद के लिए बोरे की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जायेगी। वर्ष 2007-2008 में केवल 50 कि०ग्रा० भर्ती वाले एस०बी०टी० बोरे ही प्रयुक्त किये जायेंगे। गेहूँ खरीद के दौरान प्रत्येक क्रय केन्द्र पर न्यूनतम एक गाँठ बोरे की हर समय उपलब्ध रहेगी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार बोरे की व्यवस्था रखी जायेगी। यदि राज्य सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध 13.00 लाख एस०बी०टी० बोरे के अतिरिक्त भी गेहूँ क्रय हेतु बोरे की आवश्यकता होती है तो उसे उधार-आधार पर भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त कर लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ अथवा शासन द्वारा नामित अन्य क्रय संस्थाओं को बोरो की आपूर्ति, सामांयिख नियंत्रक, द्वारा संबंधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय अधिकारी की लिखित मांग पर प्रारम्भ में अप्रैल माह की आवश्यकता के अनुसार उधार आधार पर की जायगी तथा अनुवर्ती मांग पर बोरो तभी दिये जायेंगे, जब पूर्व में उधार आधार पर दिये गये बोरो के मूल्य का भुगतान क्रय एजेंसी द्वारा कर दिया जाय। सामांयिख नियंत्रक द्वारा उपलब्धतानुसार गोदामों से आवंटित बोरो के उठान एवं आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों पर सुलभ कलाने का दायित्व संबंधित क्रय एजेंसी के जनपद स्तरीय सामान्यक अधिकारी का होगा।

12. गेहूँ खरीद हेतु धन की व्यवस्था एवं कृषकों को भुगतान

- (1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए अपने द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर जितनी मात्रा में गेहूँ की खरीद की जायेगी, उस मात्रा के लिए किसानों को भुगतान हेतु धन की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं की जायेगी।
- (2) खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों में क्रय किए जाने वाले गेहूँ के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृत कराई जाने वाली कैश क्रेडिट लिमिट से अग्रिम के रूप में धन उपलब्ध कराया जायेगा। यह धन रिवाइविंग फण्ड के रूप में रहेगा।
- (3) उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F.) के द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से रिवाइविंग फण्ड से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। क्रय किए गये गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) यदि उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ (U.C.M.F.) द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट से धन की मांग की जाती है तो इसके लिए उनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा। ब्याज की शर्तें यही होंगी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (5) राज्य सरकार की क्रय एजेंसियों (खाद्य विभाग एवं उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ) द्वारा किसानों से क्रय किए गये गेहूँ की डिलीवरी स्टेट पूल/केन्द्रीय पूल में शीघ्रता से इस प्रकार की जाएगी ताकि Flow of Funds लगातार बना रहे।
- (2) कृषकों से क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य का भुगतान करने में तत्परता सुनिश्चित की जायेगी ताकि किसी प्रकार के विलम्ब से उन्हें असंतोष न रहे। गेहूँ की खरीद सामान्यतः दृष्टि परीक्षण के आधार पर की जाती है। तदनुसार गुण निर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूँ खरीद करके, संबंधित अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि के उपरान्त कृषकों को, केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहूँ के मूल्य का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए बैंकों में "Wheat Purchase Account" के नाम से चालू खाता खोलकर क्रय एजेंसियों अपने नियमों के अनुसार कारशकारों को भुगतान सुनिश्चित करेगी। उत्पादकों/कृषकों को गेहूँ के मूल्य के रूप में मिलने वाली धनराशि की सुरक्षा की दृष्टि से रुपये 10,000/- (रु० दस हजार मात्र) तक की धनराशि के बैंक ऑर्डर अंकन तथा रुपये 10,000/- (रु० दस हजार मात्र) या उससे अधिक के बैंक "क्रासड" अंकन कर निर्गत किये जायेंगे। यदि कोई छोटा कारशकार जिसको कुल देय धनराशि रुपये 5,000/- (रु० पांच हजार मात्र) से अनधिक हो, और वह लिखित रूप से यह अनुरोध करे कि उसे ऑर्डर बैंक न देकर "बियरर बैंक" निर्गत किया जाय तो उसे बियरर बैंक दिया जा सकता है, किन्तु बैंक निर्गत करने से पूर्व उसे इस तथ्य की जानकारी दी जाए कि बियरर बैंक से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका भुगतान ले लिये जाने पर, उसकी जिम्मेदारी बैंक प्राप्ताकर्ता की होगी। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा भुगतान से संबंधित उपरोक्त सामान्य अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(3) खाद्य आयुक्त स्तर पर, स्टेट पूल में क्रय किये किये जाने वाले गोहूँ के लिए धन की व्यवस्था, सी०सी०एल० तथा सब्सिडी के माध्यम से करने, फलों ऑफ फण्ड्स बनाये रखने, सी०सी०एल० से प्राप्त धनराशि बैंक को वापस करने तथा क्रय केन्द्रों को निर्गत धनराशियों का समायोजन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियंत्रक (खाद्य) का होगा।

13. क्रय केन्द्रों पर सुविधायें

(1) क्रय एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों पर कृषकों को सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावित्त उत्तराखण्ड राज्य कृषि उत्पादक मण्डी परिषद का है। तदनुसार मण्डी समितियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में खोले गये क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख सुविधा के निमित्त निम्नलिखित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये:-

- (क) क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शनार्थ सूचनापट।
- (ख) किसानों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हेतु बाल्टी, लोटा गिलारा मिट्टी के मटके एवं वाटरमैन आदि।
- (ग) बैलगाड़ी, ट्रक, ट्राली आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्थल एवं जानवरों को पानी पिलाने के लिए नौद एवं पानी की व्यवस्था।
- (घ) कृषकों को बैठने के लिये तख्ता, दरी एवं साया के लिए शीट/शागियाना आदि।
- (च) गोहूँ की सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में दो जाली वाले उपयुक्त किस्म के छलने एवं पंखे।
- (छ) असामयिक वर्षा से कृषकों द्वारा लाये गये गोहूँ की सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में तिरपाल/पॉलीथीन शीट आदि।
- (ज) गोहूँ से भरे बोरे की शिलाई हेतु स्टैडिंग मशीन की व्यवस्था।

(2) यदि मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल अथवा उससे बाहर स्थित क्रय केन्द्रों पर मण्डी समितियों द्वारा उपरोक्तानुसार सुख सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो मण्डी समिति की ओर से यह व्यवस्था क्रय एजेंसी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जायेगी। जिसमें होने वाले व्यय का समायोजन मण्डी शुल्क से निम्नानुसार कर लिया जायेगा:-

क्र०सं०	क्रय केन्द्र पर खरीद मात्रा	अनुमन्य व्यय सीमायें
1	सीजन में 250 मी०टन तक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रुपये 5,000/- प्रति केन्द्र
2	सीजन में 251 से 600 मी०टन खरीद वाले क्रय केन्द्र	रुपये 10,000/- प्रति केन्द्र
3	सीजन में 600 मी०टन से अधिक खरीद वाले क्रय केन्द्र	रुपये 15,000/- प्रति केन्द्र

कृषकों को शासनादेशानुसार सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु उत्तराखण्ड मण्डी निदेशक द्वारा इस संबंध में अपने विभाग की ओर से मण्डी समितियों को पृथक से भी आदेश निर्गत किये जायेंगे।

14. हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान

(1) क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों द्वारा लाये गये गोहूँ की बोरे में भराई, स्टैन्सिलिंग, शिलाई, तुलाई एवं ट्रकों में लोडिंग आदि कार्यों के लिए हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य संबंधित क्रय एजेंसी द्वारा किया जायेगा। ठेकेदारों की नियुक्ति का कार्य नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये ताकि खरीद में कठिनाई न हो।

.....6.....

(2) जहाँ तक हैंडलिंग ठेकेदारों के लिये पारिश्रमिक दरों का संबंध है, इस संबंध में रायचक विचारोपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि हैंडलिंग ठेकेदारों को उनकी सेवाओं के लिए स्थानीय प्रचलित दर पर अथवा निम्नलिखित उच्चतम दरों, जो भी कम हो, के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाये:-

क्र०सं०	मद	प्रति कुन्टल अधिकतम दर (रुपये में)	
		95 कि०ग्रा०	50 कि०ग्रा०
1.	खाद्यान्नों की बोरी में मार्क लगाकर भराई, तुलाई, बॉट तथा भाप, सुतली का प्रयुक्त, 16 टॉकोईकी सिलाई	2.00	3.30
2.	भरे बोरी के स्थानीय चट्टे लगाना	0.60	1.00
3.	स्थानीय चट्टे से उठाकर ट्रक पर लदायी	0.60	1.00
4.	भरे बोरी को स्थानीय चट्टे से हटाकर गोदाम/अहाते में 16 छल्ली तक पक्के चट्टे लगाना तथा पक्के चट्टे से बोरी को उत्तरवाकर 10 प्रतिशत तौल के उपरान्त ट्रक पर लदायी	0.70	1.20
	योग:-	3.90	6.50

(3) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि प्रायः हैंडलिंग ठेकेदार कम दरों पर ठेके लेकर किसानों से अनुचित कटौतियाँ करते हैं, जिससे किसानों का शोषण होता है। ठेकेदारों की इस अनुचित प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से हैंडलिंग ठेकेदारों को 95 कि०ग्रा० तथा 50 कि०ग्रा० भर्ती के बोरी की उपरोक्तानुसार हैंडलिंग के लिये क्रमशः रुपया 2.00 एवं रुपया 3.30 प्रति कुन्टल से कम दर पर ठेका बिल्कुल न दिया जाये। ऐसे व्यक्तियों, जिनका कार्य खराब पाया जाये और उनकी शिकायतें प्राप्त हुई हो तो गुण-दोष के आधार पर भविष्य में उन्हें ठेकेदार न नियुक्त किया जाये।

(4) हैंडलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, जमानत की धनराशि जमा कराने तथा अनुबंध पत्र भरने की कार्यवाही पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-813/29-खा०-5-5(5)/89 दिनांक 07 अप्रैल, 1989 के अनुसार की जायेगी।

15. क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ के सम्प्रदान एवं बोरी की व्यवस्था हेतु परिवहन व्यय की दरों का निर्धारण तथा परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति

(1) रबी खरीद वर्ष 2007-2008 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी जिसके तहत 85 हजार मी०टन गेहूँ का सम्प्रदान स्टेट पूल में तथा क्रय किये जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के संचरण हेतु परिवहन व्यवस्था समय से की जानी अपेक्षित है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन दरों में भूकरूपता बनाये रखने के लिए ट्रान्सपोर्ट ठेकेदारों को भुगतान के लिए दरों के निर्धारण का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। दरों का निर्धारण करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा ट्रान्सपोर्ट यूनिटों से प्रचलित दरे ज्ञात की जायेगी तथा डीजल की दरों में वृद्धि आदि को ध्यान में रखकर खाद्यान्न एवं बोरी के परिवहन हेतु दरों का निर्धारण किया जायेगा।

ट्रकों की व्यवस्था के लिए शासनादेश सं०-966/XIX/2005, दिनांक 18 जून, 2005 के अनुसार व्यवस्था की जायेगी, (परिशिष्ट-2)। उक्त आदेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सांकेतिक दरों की भौति प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखकर की जायेगी।

(2) ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों को टेण्डर के आधार पर नियुक्त करने में वही मापदण्ड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो रबी खरीद वर्ष 2006-07 एवं पूर्ववर्ती वर्षों में अपनायी जाती रही है। अच्छी साख एवं ईमानदारी की साख वाले व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये तथा यथासम्भव खाद्यान्न व्यापारियों को ठेकेदार न नियुक्त किया जाये। यदि अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों में खाद्यान्न व्यापारियों को नियुक्त करना ही पड़े, तो ऐसे व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त किया जाये, जिनके विरुद्ध कोई शिकायत न हो। ठेकेदारों की नियुक्ति में गुराने, अनुभवी तथा ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाय, जिनके पास अपने ट्रक हों। इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिलाधिकारी एवं संबंधित क्रय एजेंसी का होगा कि ठेकेदार गेहूँ खरीद में विघ्नितियों का कार्य न करने पाये।

(3) नियुक्त ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों के हस्ताक्षर के नमूने एवं उनके द्वारा परिवहन कार्य में लगाये गये ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नम्बर सभी संबंधित क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ठेकेदारों को आदेश दिये जाये कि जब भी वह ट्रकों को राजकीय खाद्यान्न के परिवहन हेतु भेजे तो ट्रक ड्राइवर के हस्ताक्षर को भी अपने पैड पर सत्यापित करके भेजे। ताकि केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त ट्रक परिवहन ठेकेदार के आदेश से ही भेजा गया है।

(4) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर प्रतिदिन की खरीद के अनुपात में ट्रकों की आवश्यकता का आकलन कर अनुबंध पत्र में यह शर्त अवश्य जोड़ी जाये कि न्यूनतम ट्रकों की उपलब्धता नियुक्त ठेकेदार के पास हमेशा रहेगी। यह भी ध्यान रखा जाये कि ठेकेदार से अनुबंध पत्र भराने के बाद ही कार्य करना प्रारम्भ किया जाये।

(5) ट्रांसपोर्ट ठेकेदार से रुपये 15,000/- की नकद जमानत एवं क्रय केन्द्र पर (धिरा वर्ष अधिकतम खरीद हुई थी के आधार पर) अधिकतम 10 दिन की खरीद मात्रा के मूल्य की दस प्रतिशत धनराशि के बराबर कैडिलिटि बान्ड राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में लिया जाय। यह भी स्पष्ट करना है कि अनुबंध तथा जमानत पर स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प एक्ट की अनुसूची में निर्धारित दर के अनुसार लगेगा, जो ट्रांसपोर्ट ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिन केन्द्रों पर खरीद की मात्रा कम होने के कारण परिवहन कार्य को सन्तुल्य करने में कठिनाई हो रही हो तो वहाँ संबंधित जिलाधिकारी/संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने दिव्यक से अन्य प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए जमानत की धनराशि न्यूनतम रुपये 5,000/- तक रख सकते हैं, परन्तु जमानत कम करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्यवाही से शासन को कोई हानि न हो। यदि ट्रांसपोर्ट ठेकेदार से गेहूँ के संवर्णन में कोई क्षति होती है तो उससे इस क्षति के मूल्य के डेढ़ गुना मूल्य की धनराशि के बराबर क्षतिपूर्ति करायी जायेगी। इस शर्त को भी अनुबंध पत्र में रखा जायेगा। ऐसे सभी मामलों का विवरण संबंधित क्रय एजेंसी के वित्त नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा।

(6) उपर्युक्त विवरण के अनुसार परिवहन दरों का निर्धारण एवं ट्रांसपोर्ट ठेकेदारों की नियुक्ति तथा उनके अनुबंध भराने आदि की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित कर ली जाये।

16. क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कौटा-बॉट का सत्यापन

क्रय केन्द्रों पर प्रयोग के लिये रखे गये बॉट तथा माप का सत्यापन समय समय पर नियमानुसार नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा। संबंधित विधिक बाट माप निरीक्षक 01 अप्रैल से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि गेहूँ क्रय योजना 2007-08 में स्थापित होने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कौटा-बॉट का सत्यापन/मानकीकरण/मुद्रांकन कर दिया जाए। साथ ही समस्त क्रय एजेंसियाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि क्रय केन्द्रों पर सही बाट तथा कौटे का प्रयोग हो। किसी भी दशा में ईट, पत्थर अथवा इस प्रकार के

मानक बॉटों से भिन्न किसी भी वस्तु का प्रयोग बॉट के रूप में तौल हेतु न किया जाय। किसी भी दशा में चटतौली तथा बढतौली की शिकायत न होने पाये।

17. कय केन्द्रों हेतु भूमि का किराया

यदि किसी कय एजेंसी को कय हेतु भूमि किराये पर लेनी पड़ती है तो किराया भुगतान चराके द्वारा अनुमन्य प्रशासनिक व्यय से किया जायेगा, इसके लिए शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी। भूमि का किराया एकरूपता तथा मितव्ययिता की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा प्रति वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए निर्धारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर अधिकतम होगी।

14. कय अवधि

01 अप्रैल, 2007 से मण्डी में गेहूँ की आवक होने के साथ ही समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ कय का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और यह कय अवधि 30 जून 2007 तक रहेगी। मितव्ययिता की दृष्टि से और कम आवक के कारण यदि कोई कय केन्द्र बन्द करने की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी ऐसे कय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय स्वविवेकानुसार ले सकते हैं। सामान्यतः कय केन्द्र प्रातः 07 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खुले रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कय समय की वृद्धि की जा सकती है। रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में भी कय केन्द्र नियमित रूप से खुले रहेंगे।

23. स्टेट पूल योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ की संचरण व्यवस्था

गढ़वाल संभाग में गेहूँ की खरीद अपेक्षाकृत कुमायूँ संभाग के सापेक्ष नगण्य होने एवं गढ़वाल संभाग की विभिन्न योजनाओं में गेहूँ की केन्द्रवार आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कुमायूँ संभाग/गढ़वाल संभाग में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये गेहूँ का संचरण प्रोग्राम आयुक्त, खाद्य के स्तर से जारी किया जायेगा, जिसमें कुमायूँ/गढ़वाल संभाग के गेहूँ क्रय केन्द्रों से सीधे स्टेटपूल गोदामों हेतु संचरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, ताकि विकेन्द्रीकृत योजनान्तर्गत कुमायूँ संभाग के साथ-साथ गढ़वाल संभाग में भी आवंटन के अनुरूप गेहूँ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम, श्रीनगर हेतु गेहूँ की आपूर्ति घावल की भौति त्रिभुक्तेश्वर केन्द्र से की जायेगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक अपने-अपने संभाग में भण्डारण ऐजेन्सियों की आरक्षित संग्रहण क्षमता के पूर्ण उपयोग के साथ-साथ अन्तर-संभाग (inter-regional) गेहूँ का ऐसा संचरण/भण्डारण करावेंगे कि आन्तरिक गोदामों को गेहूँ की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

24. क्रय केन्द्रों पर अभिलेखों का रख-रखाव

प्रत्येक कय एजेंसी द्वारा कय केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अभिलेख रखे जायेंगे:-

1. आवक-क्रम-एवं टोकन रजिस्टर
2. जर्नी काश्तकार
3. क्रय पंजिका
4. स्टॉक रजिस्टर
5. रिजेक्शन रजिस्टर
6. निरीक्षण पंजिका
7. बैंक लेखा पंजी/चैक बुक/निर्गत चैकों की विवरण पंजिका
8. मूवमेन्ट चालान बुक

9. शासनादेश की पत्रावली
10. खरीद एवं सम्प्रदान के दैनिक विवरण पत्रों की पत्रावली
11. शिकायत पुस्तिका

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर रिजेशन रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका तथा शिकायत पंजिका दिखाई जायेगी।

25. खरीद प्रक्रिया

(1) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ सीधे किसानों से कय किया जायेगा। यह पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है और पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित कय केन्द्रों पर गेहूँ लाने वाले प्रत्येक किसान का गेहूँ खरीदा जायेगा चाहे वह उस संस्था/समिति का सदस्य हो अथवा नहीं। सहकारी संस्थाओं द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जायेगी कि किसान पहले उनके बकाया का भुगतान करे, तभी उनका गेहूँ खरीदा जायेगा।

(2) राज्य के सूचना विभाग एवं मण्डी परिषद द्वारा कय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा। संबंधित मण्डी समितियाँ भी इस आशय का प्रचार करेंगी कि किसान अपना गेहूँ साफ कर एवं सुखा कर कय केन्द्र पर विक्रय हेतु लाये, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो सके। यदि कृषक द्वारा साफ गेहूँ नहीं लाया जाता है तो उसे कय करने से पूर्व दो जाली वाले छलने से भली प्रकार अनिवार्यतः साफ कराकर ही कय किया जायेगा। आवश्यकतानुसार गेहूँ की सफाई हेतु कय केन्द्रों पर पंखों की भी व्यवस्था की जाये। यदि किसी कृषक द्वारा स्वयं गेहूँ साफ न करके, गेहूँ की सफाई का कार्य हैण्डलिंग ठेकेदार के माध्यम से कराया जाता है तो कार्तकार से मण्डी समिति द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित दर से सफाई का मूल्य उसके भुगतान के समायोजन द्वारा लिया जायेगा। किसी भी दशा में कय केन्द्र पर नकद धनराशि नहीं ली जायेगी।

(3) कय केन्द्र पर निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों का ही गेहूँ कय किया जायेगा। गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार अच्छे औसत दर्जे के गेहूँ का एक नमूना सील कर कय केन्द्र में पारदर्शी जार में रखा जायेगा, जो कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं माननीय जन प्रतिनिधियों को प्रदर्शित कराया जायेगा। यह नमूना कय केन्द्र पर ऐसे स्थान पर रखा जायेगा ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सैम्पल जार पर बड़े अक्षरों में "प्रतिनिधि नमूना" लिखा होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कय किये गये गेहूँ की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी कयकर्ता एजेन्सी की होगी। स्टेट फूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कभी पाई जाती है तो उसके लिए संबंधित क्रयकर्ता कर्मचारी तथा कय एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।

(4) सामान्यतः एक दिन में एक कांटे में 1,000 बोरे अर्थात् 500 कुन्तल से अधिक की तुलाई नहीं हो सकेगी। कय एजेन्सी के प्रभारी प्रत्येक केन्द्र में विपणन योग्य सरप्लस (Marketable surplus) के आधार पर कांटों की संख्या का निर्धारण कर लेंगे। कांटों की संख्या निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि इनको देखने के लिए स्टाफ पर्याप्त हो तथा कय अथवा अनावश्यक रूप से अधिक न हो जाय।

(5) जैसे ही कय केन्द्र पर किसान अपने गेहूँ का नमूना लेकर आता है केन्द्र प्रभारी द्वारा उसकी जाँच की जायेगी। केन्द्र प्रभारी के पास उपलब्ध ग्रामवार सूचियों में किसान का नाम तथा उसके पास उपलब्ध मात्रा देखकर उसका नाम पंजिका में अंकित कर लिया जायेगा और किसान को गेहूँ लाने के लिए एक तिथि दे दी जायेगी। निर्धारित तिथि को गेहूँ लाने पर किसान का गेहूँ कय कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाय कि किसानों को अनावश्यक रूप से कय केन्द्रों पर रुकना न पड़े।

- (6) गेहूँ की बोरी में भराई, सिलाई तथा स्टैसिलिंग के संबंध में निम्न व्यवस्था रहेगी :-
 (क) बोरी में 50 किग्रा गेहूँ की स्टैण्डर्ड भराई की जायेगी।
 (ख) बोरी की सिलाई मशीन अथवा 16 टाँकों से मजबूत सुतली से की जायेगी।
 (ग) प्रत्येक बोरी पर भराई की तिथि, भरते समय का वजन, कय केन्द्रों का नाम एवं जनपद/कय एजेन्सी/कय केन्द्र का कोड नम्बर अंकित होगा।

कोड नं० निम्न प्रकार होंगे :-

(अ)	कय एजेन्सी का नाम	कोड नम्बर
1.	खाद्य विभाग (विपणन शाखा)	01
2.	भारतीय खाद्य निगम	02
3.	उत्तराखण्ड सहकारी विपणन सघ	03
(ब)	जनपद का नाम	कोड नम्बर
1.	देहरादून	001
2.	पौड़ी	002
3.	हरिद्वार	003
4.	नैनीताल	004
5.	उधमसिंह नगर	005
6.	चम्पावत	006

कय केन्द्रों के कोड कय एजेन्सियों द्वारा निर्धारित कर जिलाधिकारी, साम्बागीय खाद्य नियंत्रक, भारतीय खाद्य निगम एवं शासन को दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से पूर्व सूचित किये जायेंगे।

भारत सरकार के पत्र सं०-15(10)/2003-पी०वाई०-III, दिनांक 20-11-05 के अनुसार गेहूँ के बोरी की कलर कोडिंग निम्नवत् की जायेगी:-

- प्रत्येक बोरी पर 150 मि०मी० की दूरी पर किसी भी एक छोर से "लाल रंग" द्वारा।
- स्टैसिल या ब्राडिंग "नीला रंग"।
- बोरी भरने के पश्चात् मुँह के हिस्से पर सिलाई "लाल रंग" द्वारा।
- बोरी के बीच में लम्बाई पर एक नीले रंग की अकेली स्ट्रिप होगी।

उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टैसिलिंग व सफाई न करने पर कय एजेन्सियों ठेकेदार से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियाँ करेंगी :-

क्र०सं०	विवरण	कटौती की दर
1.	खराब सिलाई 16 टाँकों से कम	रु० 0.10 पैसे प्रति बोरा
2.	स्टैसिलिंग न करना/खराब करना	रु० 0.15 पैसे प्रति बोरा
3.	गेहूँ में जीवित धुन पाया जाना (फ्यूमिगेशन चार्जज)	रु० 0.50 पैसे प्रति बोरा

(7) यदि कय केन्द्र पर किसी कारण किसान का गेहूँ अस्वीकृत किया जाता है तो रिजेक्शन रजिस्टर में कृषक का नाम, उसका पूरा पता, लाये गये गेहूँ की मात्रा, अस्वीकृत किये गये गेहूँ की मात्रा तथा अस्वीकार किये जाने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण, अस्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम अंकित किया जायेगा। इस कारण की सूचना कृषक को भी दी जायेगी। यह रिजेक्शन रजिस्टर मांग किये जाने पर संबंधित कृषक, माननीय जन प्रतिनिधिगण तथा निरीक्षकर्ता अधिकारियों को दिखाया जायेगा।

(8) कच केन्द्रों पर खरीदे गये तथा सम्प्रदान हेतु अवशेष गेहूँ की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संबंधित कच एजेन्सियों का होगा। सुरक्षा के लिए सभी वांछित उपाय कच एजेन्सी करेगी। इस पर होने वाला व्यय अनुमन्य प्रासंगिक व्यय से ही वहन किया जायेगा तथा शासन/भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मद में अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

26. भारतीय खाद्य निगम को कच किये गये गेहूँ का सम्प्रदान

(1) गेहूँ का कच विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 85 हजार मी0ट0 का सम्प्रदान/संग्रहण स्टेट पूल में तथा कच किया जाने वाला अतिरिक्त गेहूँ केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा।

(2) कच केन्द्र से स्टेट पूल डिपोज/भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक गेहूँ की दुलाई संबंधित कच एजेन्सियों द्वारा कराई जायेगी।

(3) जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कच केन्द्रों को डिपो डिलीवरी बिन्दुओं से सम्बद्ध करने के लिए मूवमेन्ट प्लान उपलब्ध कराया जायेगा। खरीदा गया गेहूँ कच केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से जमा न हो, इसके लिये आवश्यक है कि गेहूँ का संघरण खरीद केन्द्रों द्वारा खरीद के दिन से ही प्रारम्भ किया जाये।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ के सम्प्रदान/संग्रह हेतु कच केन्द्रों को स्टेट पूल से संबद्ध करने हेतु संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मूवमेन्ट प्लान तैयार किया जायेगा।

(4) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर प्रत्येक कच एजेन्सी द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जायेगा तथा भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर जो ट्रक सायंकाल 5 बजे तक पहुँच जायेगा उनकी उतराई उसी दिन की जायेगी।

(5) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ का लोडेड ट्रक पहुँचने पर ट्रक का विवरण गेट प्रवेश पंजिका में अंकित करके ड्राइवर को टोकन दिया जायेगा। जिसमें ट्रक के डिपो पर पहुँचने की तिथि तथा कम संख्या का उल्लेख होगा। भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर कम संख्या के अनुसार ही ट्रकों की अनलोडिंग की जायेगी।

(6) भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज पर गेहूँ की डिलीवरी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर दे-ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है ताकि शत प्रतिशत तौल सुनिश्चित हो सके, परन्तु जहाँ यह सुविधा न हो वहाँ गेहूँ के बोरा की 10 प्रतिशत तौल के आधार पर डिलीवरी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) भारतीय खाद्य निगम/स्टेट पूल डिपोज द्वारा स्टॉक के स्वीकृति के 24 घन्टे के अन्दर संबंधित कच एजेन्सी को गेहूँ का एक्वालेजमेन्ट दिया जायेगा तथा कच एजेन्सी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 72 घन्टे के अन्दर भुगतान कर लिया जायेगा। कच एजेन्सियों का यह दायित्व होगा कि वह भारतीय खाद्य निगम डिपोज/स्टेट पूल डिपोज से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिदिन एक्वालेजमेन्ट प्राप्त करेंगे।

27. सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता संबंधी विवाद का निराकरण

सम्प्रदान के समय गेहूँ की गुणवत्ता संबंधी विवादों के निराकरण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(1) विवाद की दशा में भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बन्धित कच एजेन्सी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए कच एजेन्सी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेगी।

स्टेट पूल में गेहूँ की डिलीवरी की दशा में खाद्य विभाग एवं सम्बन्धित कय एजेन्सी के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। इस समिति के लिए कय एजेन्सी तथा खाद्य विभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि नामित किये जायेंगे।

(2) यदि विवाद इस समिति द्वारा हल नहीं हो पाता है, तब उच्चतर समिति विवाद का निपटारा करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे : -

- (अ) भारतीय खाद्य निगम के सहायक प्रबन्धक।
- (ब) सम्बन्धित कय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी।
- (स) उप संभागीय विपणन अधिकारी।

28. खाद्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना

राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून स्थित कार्यालय में खोला जायेगा। नियंत्रण कक्ष का नम्बर 2740778 तथा फ़ैक्स संख्या 2740778 होगा। नियंत्रण कक्ष प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खुला रहेगा। इसी प्रकार संभाग स्तर पर खरीद नियंत्रण कक्ष संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में तथा जनपद स्तर पर जिलापूर्ति अधिकारियों के कार्यालयों में स्थापित किये जायेंगे। संभाग स्तर एवं जनपद स्तर से दैनिक रूप से नियमित गेहूँ खरीद से संबंधित सूचना परिशिष्ट-3 पर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। गेहूँ से संबंधित एजेन्सीवार तथा जनपदवार सूचनायें परिशिष्ट-3 के प्रपत्र में प्रभारी नियंत्रण कक्ष द्वारा अपर आयुक्त/आयुक्त को प्रतिदिन प्रस्तुत की जायेगी, तथा अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा रेडियोग्राम/फ़ैक्स के माध्यम से शासन/भारत सरकार को प्रेषित की जाया करेगी।

29. गेहूँ कय कार्य का अनुश्रवण

(1) जिला स्तर पर जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी द्वारा कय एजेन्सी एवं भारतीय खाद्य निगम के साथ सप्ताह में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार बैठक कर समीक्षा की जायेगी तथा खरीद एवं सम्प्रदान कार्य में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण एवं समाधान कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) संभाग स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा दोनों की व्यवस्था, गेहूँ खरीद तथा भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान आदि कार्यों की नियमित समीक्षा की जायेगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक तथा कय एजेन्सियों के अधिकारी नियमित रूप से भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक करेंगे और गेहूँ खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे तथा शासन को नियुक्त रूप से प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

(3) उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ द्वारा संचालित किये जाने वाले कय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद एवं सम्प्रदान कार्य की समीक्षा एवं अनुश्रवण निबन्धक उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ, अपर निबन्धक उत्तराखण्ड, सहकारी विपणन संघ तथा संबंधित सहायक निबन्धक द्वारा किया जायेगा। निबन्धक, उत्तराखण्ड, सहकारी विपणन संघ विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (गेहूँ खरीद योजना के क्रियान्वयन के संघर्ष में) निर्धारित कर परिपत्र जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध करायेंगे।

30. कय केन्द्रों का निरीक्षण

(1) सभी विपणन वर्ष सत्र 2007-08 में स्थापित कय केन्द्रों का सघन एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। संभागीय, खाद्य नियंत्रक, संभागीय विपणन अधिकारी, उप संभागीय विपणन अधिकारी, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, सम्बन्धित जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार,

खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा गेहूँ खरीद केन्द्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कृषि केन्द्र समय से खुलते हैं, उन पर अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं, किसानों से नियमानुसार गेहूँ खरीद की जा रही है और किसानों को नियमित भुगतान हो रहा है तथा खरीद प्रक्रिया में बिचौलिये कार्यरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान देखी जाने वाली मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वस्तुस्थिति का टिप्पणी में उल्लेख किया जायेगा।

(2) निरीक्षण कार्य, पीओएलएल एवं गाडी अनुरक्षण आदि पर व्यय संबंधित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किया जायेगा।

विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ खरीद व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित हो जाने की प्रत्याशा में उपरोक्त गेहूँ खरीद नीति जारी की जा रही है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी कृषि योजना 2007-08 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद की प्रभावी व्यवस्था की जाये।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जैसि)
सचिव।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

संख्या- 19/बी(1)/07-XIX-2/13 वि० (सबी खरीद)/2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि श्रृंखला लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
5. आयुक्त, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, मा० खाद्य मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम देहरादून एवं हल्द्वानी।
12. निबंधक, सहकारी विपणन संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य कुमायूँ एवं गढ़वाल सम्भाग।
14. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(एम०सी० जैसि)
अपर सचिव।